

प्रदेश 37 S

वारणसी। एसीजेम (एनएम) की कार्य में गुप्तचर दोहरा उस वक़्त अफ़सानी मच गई, जब एक महिला ने हंगामा मचते हुए आवाज़ से बाजू निकाल लिया। आनन-फ़ानन में पुलिसकर्मियों ने कस्टोडियन की सहायता में ले लिया था। निर्भयमूर्धन की 30 वर्षीय महिला दोहरा में आवाज़ कीट में पहुँच गई। अधिवक्ताओं से कहने लगी कि उसके साथ भारपीट हुई है। उस मज़मून में वे बाजू कीट के ज़रिये कैद कराना चाह रही है। अधिवक्ताओं ने उसे समझाया तो वे बाजू निकाल धमकाने लगी।

दिनांक: 19.02.2026 स्थान: मुरादाबाद प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक

माइक्रेशन सर्विफेकेट बरामद किए गए हैं। गिरोह का सरगना रौलेन्द्र कुमार ओझा है, जो गणित से एमएससी है। वह मूलरूप से रायबरेली का रहने वाला है। इस गैंग का नेतृत्व देश के तमाम राज्यो दिल्ली, मणिपुर, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, झारखंड, मध्यप्रदेश सिक्किम, छत्तीसगढ़ में फैला है।

याँचिकाकर्ता ने मुरादाबाद कैमल कोर्ट में एक अपील की जो उस अपील को चुनौती दी थी, जिसमें उसे अपनी साखी महिला को 12,000 रुपये तथा बेटे को 6,000 रुपये प्रतिमाह देने का निर्देश दिया गया था। उसका तर्क था कि विवाह केवल 18 रुपये के स्टाम्प पेपर पर हुआ, जो नहीं विवाह अधिनियम के तहत वैध नहीं है, इसलिए महिला कानूनी पत्नी नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय चमनमोहिनी बनाम चौधरी कुमार सिंह कुशवाहा का हवाला देते हुए कहा कि 'पत्नी' शब्द को व्याख्या व्यापक होनी चाहिए और पुरुष कानूनी पत्नीदाता को लाभ उठाकर जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। याँचिकाकर्ता रेलवे में लोको पावरट है और उसकी शुद्ध मासिक आय लगभग 70,000 रुपये है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार 25 प्रतिशत तक आय भरण-पोषण में दी जा सकती है। इस आधार पर 18,000 रुपये की राशि उचित ठहराई गई।

हईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि भरण-पोषण का उद्देश्य महिला और बच्चे को आर्थिक असुरक्षा और बेघर होने से बचना है। याँचिका खातिर जज कैमल कोर्ट का आदेश बरकरार रखा है।

तस्मिन् अहमद और उनके निजी मुंशी महेंद्र पाल 14 हजार रुपये की रश्मि त मांग रहे थे।
निरीक्षक नवल रायवाह के नेतृत्व में दैय-
टीम को गठन किया गया। गुरुवार को टीम ने
गुनौरी तहसील रश्मि त का कार्यालय
में दखिशा दी। जैसे ही शिकायतकर्ता ने
रश्मि त की रकम आरोपियों को सौंपी, टीम
ने उन्हें मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया।
गुनौरी इंसपेक्टर राजीव मलिक ने बताया कि
एक कथान टीम की तहरीर पर केस दर्ज
किया गया है।

येष्ठ करण ही फर्जीबाद कर चेयरमैन ने अपनी निजी संपत्ति पर करोड़ों रुपये को कार्य कराए हैं। सरकार धन का दुरुपयोग है। आरोप है कि 28 हंडेसों में भीड़ घेरोला किया गया, जिनकी वास्तविक कीमत 10 से 15 हजार है, वह 50 हजार रुपये दर्शाया गया। आरोप है कि ओपन गिन आकांक्षी योजना में भी घेरोला किया गया। इस मामले में शासन में मंडलायुक्त से रिपोर्ट तलब की गई। जिस पर कमिश्नर ने अपर आयुक्त द्वितीय से जांच कराई, जिसमें आरोपी की पुष्टि हुई है। मंडलायुक्त आन्ध्रनग्न कुमार सिंह ने बताया कि पालिकाध्यक्ष का निवर्तमान ईओ पर लगे आरोपों की जांच करवाई गई थी, जिसमें अपरा आख्या के आधार पर रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है।

- माहिला को मिलगा मरण-पोषण, शादी का ठोस प्रमाण जरूरी नहीं
- याचिकाकर्ता ने मुरादाबाद फैमिली कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी

से नहीं बच सकता। यार्थिकाकर्ता रेलवे में लोको चाकलट है और उसकी शुद्ध मासिक अवय लगभग 70,000 रुपये है। सुप्रिम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार 25 प्रतिशत तक अवय भरण-पोषण में दी जा सकती है। इस आधार पर 18,000 रुपये की राशि उचित रहणई नई।

हर्षकोर्ट ने स्पष्ट किया कि भरण-पोषण का उद्देश्य महिला और बच्चे को आर्थिक असुस्था और बेघर होने से बचाना है। यार्थिका खारिज कर फैमिली कोर्ट का आदेश बरकरार रखा है।